

सम्पादकीय



नीतीशे सरकार, भ्रष्टचार की बहार !

हम एक मुद्दत से बिहार के चुनावी हालात का विश्लेषण करना चाह रहे थे। बिहार में संभवतः नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कई मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को लेकर राजद के कार्यकर्ता 3-4 बार गालियां दे चुके हैं। कैसे लोग हैं? दो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी-ह्यावोट चोरीहूँ और बिहार के कथित अधिकार सरीखे मुद्दों पर यात्राएं संपन्न कर चुके हैं। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बेहद सचेत और परिपक्व है। जातियों और सांप्रदायिकता में पूरी तरह विभाजित है। बिहार पर करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। औसत प्रति व्यक्ति आय 3000 रुपए माहवार है। यानी 100 रुपए रोजानाङ्क! यह तो गरीबी-रेखा से निचले और भी निचले स्तर की आय है। ऐसे राज्य में एक मंत्री पर 200 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के आरोप लगें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहें। जांच एजेंसियां निष्क्रिय रहें और एक अदद प्राथमिकी भी दर्ज न की जाए, तो आश्वर्य और क्षोभ की कोई सीमा नहीं रह जाती। ह्यजन सुराज पार्टीह के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की जमीन के मामले में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पैसे और दस्तावेजों का उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और बेटी के नाम किस तरह हस्तांतरण किया गया, उसके ब्यौरे भी प्रशांत ने दिए हैं। कमाल है, किसी आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की नींद नहीं टूटी? मंत्री ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भिजवाया है। अदालत में 17 अक्टूबर को पेशी है। गंभीर आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी लगाए गए हैं कि उन्होंने एक मेडिकल कालेज पर कब्जा किया है। नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के उपमुख्यमंत्री सम्प्राट चौधरी पर एक कांग्रेस नेता की हत्या के छोटे अब भी हैं। प्रशांत ने खुलासा किया है कि उनका असली नाम राकेश कुमार है। फिर नाम बदल कर सम्प्राट कुमार मौर्य किया गया और अब सम्प्राट चौधरी है। अस्थिर यह फ्रॉड क्यों करना पड़ा? मंत्री मंगल पांडे पर भी कर्ज लेने के घपले का आर्थिक आरोप है। दिलचस्प यह है कि जनता दल-यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के.सिंह समेत एनडीए के कुछ नेताओं ने आरोपित मंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर सफाई देने की मांग की है। अलबत्ता वे अपने पद छोड़ दें। ये बेहद गंभीर राजनीतिक बयान हैं। नीरज कुमार ने इसे ह्याअग्निपरीक्षाह का दौर माना है। सरकार, अदालत और आलाकमान क्या कार्रवाई करेंगे, यह दीगर बात है, लेकिन भ्रष्टाचार अचानक बिहार चुनाव का ह्याधुरी मुद्दाह बन गया है।

विशेष

असम में घुसपैठ और बदलती सांख्यिकी पर प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश

-कातलाल माडत-

प्रधानमंत्री की अलग ही शैली रही है कि वे अनुत्तरित सवालों को नए अंदाज में राजनीतिक मुद्दों को बदलने की प्रतिभा झलकती है। देश में कई ऐसे मुद्दे आजादी के बाद अनुत्तरित चले आ रहे थे। उन मुद्दों को कानून के दायरे में रखकर उस का समाधान कर जनता के हक में फैसला दिया। मोदी ने असम में घुसपैठ करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। देश की आजादी के बाद घुसपैठ अविरल चालू है। कांग्रेस ने ऐसे ज्वलत प्रश्नों को दरकिनार कर दिया। जिन मुद्दों से जनता परेशान थी, जबकि मोदी ने दरांग में जनसभा को सम्मोहित करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की मदद से डेमोग्राफी बदलने की साजिश जोरो से चल रही है, जो रास्त्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से घुसपैठ को रोका जा रहा है। देश की जनता के साधन संसाधनों पर घुसपैठियों को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। मोदी ने असम के दरांग में हिमत विश्व सरमा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार कार्यवाई कर रही है। मोदी ने घुसपैठियों की मदद करने वालों को सीधी चुनौती देते हुए कहा, पड़ोसी देशों के घुसपैठियों को हटाने ने लिए हम अपना जीवन लगा देंगे। घुसपैठियों और साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मोदी ने दरांग की सभा में हुंकार भरते हुए कहा कि यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। असम में घुसपैठियों के पनाहगाह को देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ने दरांग में घुसपैठियों का असम का दूसरा नाम दिया।

कांग्रेस पर साथा हमल करत हुए अपन सम्बवधन म कहा कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब घुसपैठियों को सरकार देती थी। क्योंकि कांग्रेस यह चाहती है कि घुसपैठिये हमेशा के लिए भारत मे बस जाए और भारत का राजनीतिक भविष्य तय करे। कांग्रेस के लिए देशहित मे बड़ा, अपने वोटबोक का हित रहा है। लेकिन मोदी ने कहा कि अब यह नहीं चलेगा। कांग्रेस गफलत की राजनीति की मास्टरमाइंड है। पूर्वोत्तर राज्यो में स्थानीय बनाव विदेशी नागरिकों का मसला एक समस्या बन गया है। देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कोताही नहीं बरतेगी। क्योंकि घुसपैठ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हर जगह पर अपना प्रभाव छोड़ता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि पर घुसपैठियों का परिवार निर्भर रहता है। असम मे घुसपैठियों ने संशाधनों पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं कृषि भूमि भी अपने अधीन करते जा रहे हैं। असम सरकार का मिशन है कि डेमोग्राफी बदल रहे हैं। घुसपैठियों को खेड़ा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमत बिस्वा सरमा बड़ी तल्लीनता से घुसपैठ को बाहर करने मे लगे हुए है। बड़ी संख्या मे घुसपैठ कर लोगों के आजीविका के साथों पर अपना हक जमाना शुरू कर रहे हैं। बहरहाल, असम के मुख्यमंत्री का घुसपैठ पर उनका मत स्पष्ट है कि घुसपैठियों और बोडो आदिवासियों के बीच समय समय पर हाथापाई होती है। जिससे आदिवासियों को बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है। 1971 से पहले रह रहे नागरिकों के लिए वैधता सुनिश्चित की गई है। 1971 के बाद आने वाले घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की मुहिम चालू है। घुसपैठ की यह विडंबना रही है कि कांग्रेस ने इनका कभी विरोध नहीं किया। असम मे 40 लाख नागरिकों को अवैध श्रेणी मे रखा गया है। देश मे जन सांख्यिकी को बदलने की चेष्टा करने वालों के मुह पर असम के मुख्यमंत्री हिमत बिस्वा सरमा का करारा तमाशा है। अमित शाह ने कहा था, यह भारत धर्मशाला नहीं है, जो भी आया, वो यहां बस गया। घुसपैठ को खेड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। अपनी नागरिकता सिद्ध करने का सरकार मौका दे रही है। उसके बाद भी नागरिकता सिद्ध नहीं करने वालों को अपने वतन फिर भेजा जा सकता है। राजनीतिक दल अपने बजूद बचाए रखने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठ को बढ़ावा देकर अवैध नागरिक को वैध घोषित करने की नाकाम कोशिश करते आ रहे हैं। यह शर्मसार है और घटिया मानसिकता है। पिछले 20 सालों मे असम की जनसंख्या मे बड़ा बदलाव हुआ है। इस दौर मे 51 प्रतिशत जनता की बढ़ोतरी देखकर सरकार के खान खड़े हो गए। यह चौकाने वाले आंकड़े हैं। जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। 1971 से 1991 के बीच 89 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई। 1991 मे असम मे हिन्दूओं की जनसंख्या वृद्धि 41.89 फीसद थी, वही मुस्लिम समाज की 77.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यह आंकड़े चौकाने वाले हैं। असम मे जनसंख्या वृद्धि से स्थानीय आदिवासी लोगो के साथ दुर्व्यवहार और सम्प्रदायिक दंगों का कारण रहा है। केंद्र सरकार घुसपैठ पर विशेष ध्यान देकर स्थानीय लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करे। पूर्वोत्तर राज्यो मे पश्चिम बंगाल मे घुसपैठ की संख्या बहुत है।

जातिवाद पर प्रतिबंध योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम

-ललित गग्नी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ ने हाल ही में
एक ऐतिहासिक और
साहसिक कदम उठाया है।
उहोंने समाज में जाति आधारित विद्वेष के

हजारतवाद समाज का आत्मा का खासखला करता है। हड्डों भीमराव अंबेडकर ने तो इसे भारतीय प्रगति की सबसे बड़ी भावधा बताया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी जातिवाद ने राजनीति और समाज दोनों में गहरी पैठ बनाई और देश की एकता को कमजोर करने का काम किया। जाति-आधारित राजनीति ने सत्ता के समीकरण तो बदले लेकिन समाज को बांटने का काम किया। चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरणों के आधार पर होता रहा। समाज के बंटवारे का यह खेल लोकतंत्र के स्वरूप आदर्शों के लिए चुनौती बना। जातिगत रैलियां और प्रदर्शन सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते रहे। पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख अपराधी को अपराधी नहीं बल्कि किसी जाति का प्रतिनिधि बना देता था, जिससे कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था। इन जटिल स्थितियों में योगी सरकार का यह निर्णय विषमताओं एवं विसंगतियों को समाप्त करने की दिशा में एक नया अध्याय है। यदि इसे सख्ती और ईमानदारी से लागू किया गया तो निश्चित ही समाज में सौहार्द, भाईचारा और समानता का वातावरण बनेगा। जाति-आधारित पहचान की जगह व्यक्ति की योग्यता, आचरण और योगदान को महत्व मिलेगा।

किसी जाति के प्रति लगाव दशार्ने के लिए किसी अन्य जाति को नीचा दिखाने की भी गलत परंपरा पड़ती दिख रही है। जाति आधारित पोस्टर या प्रतीक न केवल गलियों में, मकानों पर बल्कि अपने वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में, परस्पर भेद, ऊंच-नीच की भावना बढ़ती जा रही है। ऐसे भेद को मिटाने की मांग उठती रही है। समाज के लिए चिंतित रहने वाले लोग यहीं चाहते हैं कि जातिगत झंडों और पोस्टरों पर एक हृद तक लगाम लगाना चाहए, लाकन एसा साहस राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब तक किसी भी राजनेता ने नहीं दिखाया, लेकिन योगी सरकार ने यह साहस दिखाया है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। योगी सरकार द्वारा जारी 10 सूत्रीय दिशा-निर्देश में यह बात विशेष रूप से गौर करने लायक है कि अब जाति के नाम, नारे या स्टिकर वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान किया जाएगा। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जाति को दशार्ने से बचा जाएगा। अभी तक होता यह है कि अपराधी जाति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं और मजबूत हो जाते हैं।

यह बहुत अफसोस की बात है कि विशेष रूप से चुनाव के समय जाति आधारित बैनरों की बाढ़ आ जाती है। राजनीतिक दल एवं नेता जातिगत समीकरणों से समाज को बांटने में जुट जाते हैं। लेकिन अब यूपी सरकार की मंशा सराहनीय है और इन दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। वाकई समाज से अपराध को मिटाने के लिए अपराधी की जाति देखना गैर-वाजिब है। हाँ, यह सावधानीपूर्वक कुछ मामलों में जाति का उल्लेख करने की छूट दी गई है। जैसे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल होता रहेगा। वाकई, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जहां जाति की चिंता या उल्लेख जरूरी हो जाता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि जाति आधारित भेदभाव अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल जाता है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर भेदभाव की शिकायतें अवसर आती हैं, ऐसे में, प्रशासन को ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। निर्देश जारी हो जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव के बिंदुओं का खाज-खाजकर प्रमाणन का इमानदार पहल भी जरूरी है। सामाजिक चिंतक विनोबा भावे कहा करते थे हजारित का भेद मिटेगा तो समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना पनपेगी। हाँ वास्तव में जातिवाद केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानसिकता का रोग है। जब तक समाज इसे स्वीकार करता रहेगा, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, अपने राजनीतिक जीवन के अनेक उदाहरणों से समाज को सक्रिय प्रशिक्षण भी दिया। वे समता के पोषक हैं, इसलिये उन्होंने पूरी शक्ति के साथ जाति के दंश, प्रथा एवं विसंगति पर प्रहार कर मानवीय एकता का स्वर प्रखर किया। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिससे राज्य में अपराध और अराजकता पर काफी हृद तक नियंत्रण पाया गया। हँसबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास ही नीति पर चलते हुए उन्होंने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की। बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक स्थलों के पुनरोद्धार, निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। उनकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकासशील राज्यों में गिना जाने लगा है और जातिवाद, भ्रष्टाचार और असुरक्षा की छवि से बाहर निकलकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उनकी ताजा पहल समाज को बताती है कि नई पीढ़ी को जाति नहीं, योग्यता और नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यह निर्णय राजनातक दलों के लिए भा चेतावनी है कि उन्हें जातिगत समीकरणों की राजनीति छोड़कर राष्ट्रहित और जनहित की राजनीति करनी होगी।

जाति, रंग, भाषा आदि के मद से सामाजिक एवं राजनीतिक विक्षेप भैंसा होता है, इससिलिये यह पाप की परम्परा को बढ़ाने वाला पाप है। इसके कारण राष्ट्रीयता को भूल कर जातिगत संकीर्णताओं को लोग आगे बढ़ाते रहे हैं, एक जाति के लोग मजबूत होने के बाद वे अपनी जाति को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हृद तक जाने को तैयार रहते हैं। यह धारणा भी बढ़ती रही है कि सबको अपनी जाति की चिंता करनी चाहिए। यह भ्राति भी फैल रही है कि अपनी जाति के लोग या अधिकारी या नेता ही अपनी जाति के समुदाय या लोगों की मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। ऐसे तमाम सामाजिक व प्रशासनिक खामियों एवं विद्यमानों से उबरने की जरूरत योगी सरकार ने महसूस की है। अन्यायी के खिलाफ बिना जाति देखे खड़ा होना चाहिए। सर्विधान की भी मंशा यही है कि हर नागरिक को अपने समाज की ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए और ध्यान रहे, यह समाज मात्र एक जाति आधारित न रहे। हर जाति महत्वपूर्ण है और सबका विकास हो, पर जाति आधारित लगाव या राजनीति का दिखावा खत्म होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम भारतीय समाज को जातिवाद की जंजीरों से मुक्त करने का बड़ा अवसर है। यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। अब आवश्यकता है कि अन्य राज्य भी इसे अपनाएं और भारत को सच्चे अर्थों में समानता, न्याय और बंधुत्व की धरती बनाएं।

धर्म का पागलपन और आहत भावनाएँ

- सवामत्रा सुरजन

ध म आतंकवाद पर जोर देता है, लेकिन इस समय केवल दिखावा और दबंगई धर्म के नाम पर हो रही है। जैसे एक बार फिर नवारात्रि में देश के कई हिस्सों में मांस-मछली, अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि बड़ी आबादी समिध भोजन करती है। मान लें कि नौ दिन वे मांस के सेवन के बिना रह भी लें, लेकिन जो विक्रेता हैं, उन्हें किस बात का अधोविष आर्थिक प्रतिबंध सहना पड़ रहा है। जिन लोगों का घर रोज की कमाई से चलता है। अमेरिका में सतारुद्ध रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने टेक्सास में लगी भगवान हनुमान की प्रतिमा पर विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया न्लेटफार्म एक्स पर डंकन ने लिखा— हम टेक्सास में एक झूटे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति करों लगाने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ईसाई राष्ट्र नहीं है, हालांकि वहां ईसाई बहुल आबादी है। अमेरिकी संविधान में एक एस्ट्रेब्लिशमेंट क्लॉज है, जो कहता है कि सरकार किसी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दे सकती। इस लिहाज से अमेरिका धार्मिक राष्ट्र नहीं, बल्कि धर्मनियन्पेक्ष लोकतंत्र है। ठीक वैसे ही जैसे भारत

हूं बहुत आकर्षणीय है। लागत नहीं धिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र नहीं भारत का संविधान किसी धर्म को धिकारिक धर्म की मान्यता नहीं देता है, बल्कि संविधान की विवादों में ही बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह इसलिए याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डंकन के इस देश पर कई लोगों की भावनाएं हत हो गई हैं और कुछ हिंदू गढ़ोंनों ने इस का विरोध भी किया बता दें कि टेक्सस के शुगर लैंड 2024 में हुनुमान जी की 90 फीट ऊपरी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसे 'स्टैच्यू आफ यूनियन' न दिया गया है। इस कांस्य प्रतिमा श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित या गया है। इसे अमेरिका की परी सबसे ऊँची प्रतिमा माना जाता है।

अमेरिका की संस्था हिंदू परिक्रमन फाउंडेशन ने डंकन के बान को हिंदू विरोधी बताया है। वह कोई उन्हें बताए कि भारत में क्या ऐसा ही पागलपन हर दूसरे दिन बने मिलता है, तब कितनों की विवादों आहत होती हैं। अब तो नहीं आहत भावनाओं का इजहार अपराध बना दिया गया है। अमेरिका में फिलहाल हालात हमसे बदलते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के बाते कब तक हालात अच्छे बने गे, कहा नहीं जा सकता। डंकन समर्थक हैं और वो अमेरिका को इसाई भृत्यों द्वारा करार भव दखना चाहते हैं। वैसे ही जैसे भारत में मोदी समर्थक बार-बार इच्छा प्रकट करते हैं कि भारत की हिंदू राष्ट्र धोषित किया जाना चाहिए। मोहन भागवत जैसे लोग तो यही मानते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं। वैसे अमेरिका में केवल हिंदू संगठनों ने ही नहीं, कई अन्य संगठनों ने भी इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए माफी की मांग की है। बहुत से अमेरिकी नागरिकों ने भी इसकी घोर निंदा की है। और ये वो लोग हैं, जो हर किस्म की धार्मिक कटूरता का विरोध करते हैं। इन्हीं लोगों के कारण असल में अमेरिका आज उस मुकाम पर पहुंच पाया है, जिसे असल मायने में विश्वगुरु कहते हैं। अधिव्यक्ति की आजादी, हर किस्म के श्रम का सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, कला, संस्कृति में नित नवाचार से हीता विकास, मानवाधिकारों की मजबूती, ऐसे कई कारक हैं, जिनके कारण अमेरिका विकसित हुआ और यहां जीवनस्तर बेहतर हुआ। वेशक हर देश की तरह अमेरिका भी कई किस्म की कमजोरियों और समस्याओं का शिकार है। लेकिन फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कई मायनों में अमेरिका हमसे कहीं आगे है। ऐसा नहीं है कि भारत उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, आजादी के बाद भारत ने जितनी जल्दी जाता नहीं है। वैसे ही जैसे भारत में मोदी धार्मिक उन्माद देखने मिल रहा है। यह सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और पिछले 11 सालों से इसमें तेजी आ गई है। यह कहने में कोई संकेत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में धर्मांधता को जी भर के बढ़ावा मिला है। इस दौरान जितनी धर्म संसर्दे हुई, धार्मिक जुलूस निकले, सार्वजनिक पूजा पाठ के कार्यक्रम हुए, सबमें किसी न किसी तरह अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का काम किया गया। इंद के वर्क मरिजदों के सामने शोर, क्रिसमस के वर्क चर्चों के सामने तमाशे किए गए और अब इस बात का बुरा माना जा रहा है कि अमेरिका के एक शहर में लगी हुनुमानजी की मूर्ति पर किसी अमेरिकी नेता ने बयान क्यों दिया। धार्मिक आजादी और मानवता किसी भी लिहाज से यह बात सही नहीं है, लेकिन इस कड़ी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि जैसे कई हिंदू दूसरे धर्म के ईश्वरों, देवदूतों को मान्यता नहीं देते, सम्मान नहीं देते, वैसे ही दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के भगवानों, देवताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं। कोई भी धर्म अनुयायी किसी अन्य धर्म अनुयायी की आस्था और विश्वास को ठेस न पहुंचाए, वही आदर्श श्रिति है। सारे धार्मिक ग्रंथ यही शिक्षा देते हैं। लेकिन राजनैतिक लाभ और सत्ता की खातिर धर्म की गलत व्याख्या की जा रही है। बन जातारक यापना पर जा दिया है, लेकिन इस समय के बल दिखावा और दबंगई धर्म के नाम पर हो रही है। जैसे एक बार फिर नवारात्रि में देश के कई हिस्सों में मांस-मछली, अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि बड़ी आबादी सामिध भोजन करती है। मान लें कि नौ दिन वे पासंस के सेवन के बिना रह भी लें, लेकिन जो विक्रेता हैं, उन्हें किस बात का अधोषित अर्थक्रिया प्रतिबंध सहना पड़े रहा है। जिन लोगों का घर रोज की कमाई से चलता है, उन लोगों को नौ दिनों तक फाकाकशी में रहना पड़े, यह किस भगवान को मंजूर होगा। तृणमूल कांग्रेस की संसद महआर्मेंट्रा ने भोपाल में ऐसी ही प्रतिबंध भोपाल को कैसे सिर्फ इसलिए मछली, मांस और अंडे छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है क्योंकि कुछ लोग साल के बाकी दिनों में किए गए अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ समय के लिए शाकाहारी बनने का फैसला करते हैं? मध्यप्रदेश- यही पागलपन के बल दिलता है जब आपको तब मिलता है जब आप भाजपा को बोट देते हैं। हालांकि ये पागलपन के बल मध्यप्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। कौन सी जुबान बोलेगा, किस तरह अभिवादन करेगा, इस पर अब धर्मांधता से भरे फूरमान आने लगे हैं।

राजनीतिक द्वेष का शिकार हो गए आजम खान

-दिलीप कुमार पाठक

झे मार दिया जाए,
मेरी यूनिवर्सिटी में
बुलडोजर चला
दिया जाए फिर भी एक यूनिवर्सिटी
के फाउंडर के रूप में मेरी शिनाख्त
होगी। मुझ पर किताबों की चोरी का
आरोप लगाया गया है, अगर चोरी
करके कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता
है तो ऐसे चोरों की जरूरत हिन्दुस्तान
को है। ये शब्द किसी और के नहीं
बल्कि उत्तरप्रदेश के सबसे चार्चित
दिग्गज नेता आजम खान के हैं।
मुहम्मद आजम खान एक तेजतरार
नेता आपातकाल की छाया से
निकलकर उत्तर प्रदेश की सबसे
मजबूत राजनीतिक आवाजों में से
एक बनकर उभरे थे। आजम खान
मुल्क के दिग्गज नेताओं की
फ्रेंचरिस्ट में शामिल रहे, जिन्होंने
नम्बा दौर सियासत के आंगन में
जिया, परंतु उनके हिस्से लम्बा संघर्ष
भी आया... उत्तरप्रदेश में जिनकी
नूती बोलती थी, जिनकी पासैनेलिटी
रेपो कि जिस गली से गुजर जाएं तो
गुलूस निकल जाए। मुँह खोलें तो
हड लाइन बन जाए। उत्तरप्रदेश का
ऐसा नेता जो पूरे देश की राजनीति के
केंद्र में होता था। आपातकाल में
इन्दिरा गांधी के मुखर विरोध में

गिरी में कूद जाने वाले आजमन ने कभी भी राजनीतिक झौता नहीं किया, कीमत चाहे भी रही हो। आजम खान ने गरीबों उंगली थामकर नवाबों के राजनीतिक किले की प्राचीर को स्त कर दिया था। इंदिरा गांधी के ढह आवाज बुलन्द करने वाले जम खान को काल कोठरी में टूस गया था, जहां इंसानों को रखने मनाही थी जो बिल्कुल जायज थी। जहां उनके साथी नेताओं आरामदायक जगह में रखा गया वहाँ आजम खान ने तमाम दृष्टियां झेली... आपातकाल के अन 17 महीनों की लम्बी कैद नने के बाद पहला चुनाव जनता नींहीं की टिकिट पर लड़ गए हार का मना करना पड़ा था, लेकिन नींहीं से जूझते रहे। हार ने उनके इरादों को और बूत कर दिया और उन्होंने रामपुर नवाब परिवार के प्रभुत्व को खुली नींहीं देने का फैसला किया। नवाब वार ने ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजों साथ दिया था और बाद में नींहीं में अपना दबदबा बनाए था। जुलिफ़ कार अली खान ने 67 से 1989 तक रामपुर से संसद सीट पर कब्जा किया, और की पत्नी नूर बानो ने 1996 और

आजम खान का प्रभाव बढ़ने के साथ, रामपुर पर नवाबी पकड़ कम होती गई। 1980 से 1992 के बीच, खान ने चार अलग-अलग दलों के टिकट पर रामपुर सीट जीती। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद, वे मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गए और पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। 1999 में जीत हासिल की। आजम ने इस नवाबी दबदबे को चुनौती देने का बीड़ा उठाया, और खुद को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया। 1980 में, आजम ने रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, उन्होंने मजदूरों और निचले तबके के बीच अपना समर्थन मजबूत करना शुरू किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के आदर्शों से प्रेरित होकर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आजम ने रामपुर के मजदूर वर्ग को संगठित किया और नवाबी परिवार के प्रभुत्व को चुनौती दी। आजम खान का प्रभाव बढ़ने के साथ, रामपुर पर नवाबी पकड़ कम होती गई। 1980 से 1992 के बीच, खान ने चार अलग-अलग दलों के टिकट पर रामपुर सीट जीती। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद, वे मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गए और पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। उनकी लगातार जीत और तीक्ष्ण भाषण कला ने उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक बना दिया। 2003 में, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, आजम खान ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की और रामपुर में एक विश्वविद्यालय की नींव रखी। विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सपा कैबिनेट की उपस्थिति खान के प्रभाव को दर्शाती थी। लेकिन 2017 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर को किंतब चोर कहकर चिड़ाया जाने लगा। ये भी राजनीति का क्रूर चेहरा है। मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम खान हमेशा उनके बाद वाली मजबूत पोजीशन वाले लीडर रहे, परंतु समाजवादी पार्टी में पांची परिवर्तन होता गया, खुद को आजम खान परिस्थितयों में ढालते रहे, परंतु मुलायम सिंह यादव ने हमेशा आजम खान को अपने भाई के बराबर स्नेह दिया। उन्हीं आजम खान को मुलायम सिंह के निधन के बाद दरकिनार कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी से सीमित समर्थन के बावजूद, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती चली गईं, जेल में रहने के दौरान अखिलेश यादव और पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। हालांकि वे एक अपराधी नहीं, बल्कि एक राजनेता के रूप में उभरे और आपातकाल के दौरान जेल गए थे। भाजपा के प्रभुत्व और उनके खिलाफ 100 से अधिक कानूनी मामलों के बावजूद, उनका प्रभाव और रामपुर में चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता बनी हुई है। अदालत के फैसले इस बात की तस्वीर करते हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक विद्रोह के कारण तमाम मुकदमे लादे गए। हालांकि बात मुकदमों की नहीं है, बात उनकी विश्वसनीयता की है, एक पूर्व मंत्री कई बार के सांसद, एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर ने मुर्गी चुराई, बकरी चुराई, भैंस चुराई, उनकी पत्नी ने कुछ पैसे चुराए, उनके बेटे ने शराब की बोतलें लूटी... हमारे देश की राजनीतिक द्वेष भावना को देखना हो तो इस स्तर पर जाकर समझ सकते हैं.. आजम खान में तमाम दोष हो सकते हैं परंतु एक चेतना सम्पन्न आदमी अगर इसका मूल्यांकन करे तो समझ आएगा क्या आजम खान के लिए यही काम रह गया था कि वे मुर्गी, बकरी, चौरी करेंगे ? ऐसे घिनौने आरोपों के बावजूद आजम खान की शिख्सयत कभी धूमिल नहीं हुई। उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगे, उनकी जांच विमर्श कोर्ट करेगा, परंतु इस तरह राजनीतिक द्वेष के तहत जेल में दूसरे देना क्या यही भारतीय राजनीति का स्तर है ? यही कारण है कि जेल से छूटने के बाद आजम खान ने कहा था मैं गूँगा हूँ, मेरे मुँह में जुबां नहीं हैं, मैं अंधा हूँ, मेरी आँखों में रोशनी नहीं है, जेहन खाली है क्योंकि मेरे बुद्धि नहीं है। इतना फना कर दिया गया हूँ और कितना किया जाऊँगा... कोई बता सके तो बताए... हालांकि इतना कहूँगा मेरे पास इमान है। आजम खान की शिख्सयत बेजोड़ है, आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं परंतु अनदेखा नहीं कर सकते। आजम खान ने अपराध किए था नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, परंतु ये तय हो गया है कि भारत की राजनीति का स्तर बहुत घिनौना है।

